(ii) जनजातीय क्षेत्रों मे सभी एक्सचेंजो को आटोमेटिक बनाना ।

(iii) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र मे सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों मे जो दूर संचार सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न नुसार है :--

क्र०स०	मद	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	बिहार
1.	निवल स्थानीय स्विचन क्षमता	21150	52000	19100
2	सीधी एक्सचेज लाइनें	14800	41700	18500
3.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	प्रत्येक ग्राम पचायत मे एक		

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अनुदान

744 **श्री अजीत जोगी** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सडक निधि के अंतर्गत 3 अक्तूबर, 1989 को केन्द्र सरकार के पास वर्ष 1989-90 तथा आठवी पचवर्षीय योजना के लिये 92 83 करोड रुपये के प्रस्ताव भेजे गये है ,

(ख) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा 500 से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी ग्रामो को मुख्य मार्गों से जोडने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति/वित्तीय सहायता हेत् भेजा हैं ,

(ग) मध्य प्रदेश शासन को उक्त राशि उपलब्ध कराने हेत् केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा और यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी, और

(घ) क्या 500 से कम जनसख्या वाले आदिवासी ग्रामों को भी सडको से जोडने के बारे मे केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ मे जल-भतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग को, जो कि नॉडल मत्रालय है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है, तथापि, वे आदिवासी ग्रामों को जोडने के लिए कोई योजना नही चला रहे है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सडक निधि मे वास्तविक वृद्धि, जिसके आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी नहीं हुई है इसलिए इन प्रस्तावो पर अनमोदन के लिए कार्यवाही नही की गई है ।

(घ) जी, नही ।

मध्य प्रदेश में सड़क विकास के लिये विश्व बैंक सहायता

745. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **जल-भतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश सरकार की इस वर्ष सडक विकास के लिये विश्व बैंक से कुल कितनी ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना है ,